सांध्य दैनिक

4PM

अज्ञानी व्यक्ति काम कम और बातें अधिक करते हैं।ऐसे लोग खुद अपना तर्क रखने के बजाय सुनी सुनाई बातों को ही रटते रहते हैं।

-कबीर दास

मूल्य ₹ 3/-

जिद...सच की

www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_Sanjay YouTube @4pm NEWS NETWORK

● वर्ष: 10 ● अंक: 40 ● पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, मंगलवार, 12 मार्च, 2024

सूर्यकुमार आईपीएल के शुरुआती मैच नहीं... 7 | सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मचेगा... 3 | भाजपा को सत्ता से बेदखल... 2

देशभर में 4PM यूट्यूब चैनल पहले नंबर पर

बड़े-बड़े दिग्गजों को छोड़ा पीछे

साढ़े दस करोड़ व्यूज आये एक महीने में

नामी चेहरे पीछे छूटे 4PM का डंका बजा पूरी दुनिया में

» सत्ता के कारनामे आगे लाता है 4पीएम न्यूज नेटवर्क

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। मनमानी कर रही सत्ता को खबरों की सच्चाई से अंकुश लगाने की कोशिश में जुटे जन-जन के पसंदीदा यूट्यब चैनल 4 पीएम ने एक बार फिर सबको पीछे धकेलते हुए अपनी धाक जमाई है। सच को आम जनतक पहुंचाने की मुहिम में जुटे 4 पीएम ने फरवरी के महीने में 33 लाख सब्सक्राइबर के साथ सभी दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है।

4 पीएम ने डीबी लाइव व अन्य बड़े यूट्यूब स्टारों को भी पीछे करके अपनी लोकप्रियता में चार चांद लगा लिए हैं। यहीं नहीं अपने बेबाक रिर्पोटिंग की वजह से चैनल के व्यूज में भी उत्तरोत्तर जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। पिछले कई महीनों के भीतर इसकी संख्या में लागातार बढ़ोत्तरी हो रही है। गौरतलब हों सत्ता से सवाल करने की आदत और सच को दिखाने की जिद का ही नतीजा है कि 4पीएम दिनो-दिन आगे बढ़ता जा रहा है। इससे पहले भी 4पीएम यूट्यूब चैनल देश का नंबर वन चैनल बना था। सच दिखाने की बदौलत ही 4पीएम को लगातार दर्शकों का प्यार मिल रहा है और 4पीएम आए दिन नई-नई बुलंदियों को छू रहा है।

डाटा बिंग्स के ताजा आंकड़ों में चैनल व्यूज के मामले में टॉप पॉलिटिकल कमेंटेटर्स की श्रेणी में देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाले यूट्यूब चैनल बना हुआ है। इसी क्रम में पिछले कुछ एक महीनों से नंबर 2 पर चल रहा 4पीएम अब नंबर वन का यूट्यूब चैनल बन गया है। चैनल की लोकप्रियता का ही असर है कि इसकी मांग अन्य कई राज्यों में होने लगी है। लोगों को चैनल के हर कंटेंट पंसद आ रहा है, और लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ रहे हैं।

33

लाख सब्सक्राइबर जुड़े, लोगों की पसंद बना चैनल

Top Political Commentators on YouTube - Views Market Share (January 2024)

Excl. mainstream media. View count as of Feb 25 for Jan uploaded videos only

databeings — Colors indicate political leaning

Rank	Channel	#Views (Million)	Views Share	Rank	Channel	#Views (Million)	Views Share
1	4PM	100.2	7%	16	The Chanakya Dialogues Hindi	34.8	3%
2	DB live	98.5	7%	17	CAPITAL TV	33.9	2%
3	Headlines India	95.0	7%	18	FreeZ Hindutva	33.4	2%
4	BR Amazing facts	89.8	7%	19	Deepak Sharma	32.7	2%
5	Abhisar Sharma	88.1	6%	20	Forum4 News	31.7	2%
6	NMF News	80.7	6%	21	Article19India	30.6	2%
7	National Dastak	54.0	4%	22	Khabar India ख़बर इंडिया	30.1	2%
8	Ulta Chasma uc	46.6	3%	23	The Janta Live	27.2	2%
9	EXPLICIT WORLD	44.8	3%	24	Punya Prasun Bajpai	27.2	2%
10	Ravish Kumar Official	44.4	3%	25	KADAK	25.1	2%
11	Unite India	43.5	3%	26	Online News Bharat	25.1	2%
12	Ajit Anjum	43.5	3%	27	Satya Hindi	24.8	2%
13	The News	40.3	3%	28	Ds4 News	24.5	2%
14	Online News India	39.7	3%	29	Pyara Hindustan	23.2	2%
15	Earth 24	38.1	3%	30	The Jaipur Dialogues	22.6	2%
					Total	1374.1	100%

Note: We have significantly expanded our master list for channel tracking. Top 30 shown here.

thedatabeings.com contact@thedatabeings.com @DataBeings

नहीं रुकेगा तीखे सवाल पूछने का सिलसिला

4पीएम की बढ़ती लोकप्रियता ये दर्शाती है कि सत्ता से सवाल करना लोगों को आज भी पसंद है। हर कोई सच को ही देखना चाहता है। बस कोई सच दिखाने वाला हो। 4पीएम की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है और कीर्तिमानों की नई ऊंचाईयों पर चढ़ता जा रहा है। लोगों के मिल रहे प्यार का ही नतीजा है कि 4पीएम की श्रृंखलाओं में भी आए दिन बढ़ोत्तरी हो रही है। वर्तमान समय में 4पीएम नेशलन के अलावा सात राज्यों के भी क्षेत्रीय यूट्यूब चैनल चल रहे है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए 4पीएम बॉलीवुड का भी चैनल चल रहा है। यही वजह है कि देखते-देखते सब्सक्राइबर्स की संख्या 3.3 मिलियन के करीब पहुंच गई पता ही नहीं चला।

सच के साथ खड़े होते हैं लोग

लोगों के प्यार और अपने सच दिखाने की जिद की बदौलत 4पीएम लगातार सफलता की सीढ़ियों को चढ़ रहा है और देश में आए दिन अपना परचम फहरा रहा है। जिस समय देश की कथित मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ सत्ता वंदन में लगी हुई है, ऐसे में 4पीएम और उसके संपादक संजय शर्मा ने अपने यूट्यूब चैनल के जरिए सत्ता से तीखे सवाल करना जारी रखा और जनता के सामने लगातार सच को दिखाते रहे हैं। आज उसी सच और सत्ता से सवाल करने के हौसले का ही नतीजा है कि 4पीएम देश भर में अपनी अलग पहचान बना रहा है। निरंतर अपनी लोकप्रियता में दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ोत्तरी कर रहा है।

हरियाणा में सियासी हलचल

खट्टर ने सीएम पद छोड़ा

» पूरे मंत्रिमंडल के साथ राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा

» जेजेपी और कांग्रेस ने अपने विधायकों को दिल्ली बुलाया

» कांग्रेस बोली- चुनाव से पहले बीजेपी की चालबाजी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चंडीगढ़। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी भूचाल आ गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को अपना इस्तीफा सौंप दिया। खबरों के मुताबिक, जननायक जनता पार्टी से रिश्ते टूटने की आशंका के बीच बीजेपी नेतृत्व हरियाणा सरकार में कुछ बड़े बदलाव कर सकता है। उधर विपक्ष ने इसके पीछे बीजेपी की चाल बताया है।

सूत्रों के अनुसार नायब सिंह सैनी, जो गैर-जाट हैं, उनकी जगह लेंगे। सूत्रों के मुताबिक मनोहर लाल खट्टर करनाल से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से ख़बर है कि मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने रहेंगे। साथ ही अलग अलग समुदायों से दो उपमुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं हरियाणा में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव कराने का विचार किया जा रहा है।

मैने तो पहले ही कहा था टूटेगा गठबंधन : हुड्डा

हरियाणा पर हुए घटनाक्रम पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता दिपेंदर हुड्डा ने कहा है कि उन्होंने तो पहले ही कहा था कि लोक सभा चुनाव से पहले जेजेपी व बीजेपी गठबंधन टूट जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनावों में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब जुगत की जा रही है। हुड्डा ने कहा कि जेजेपी व आईएनएलडी अलग-अलग चुनाव लड़ेगे और बीजेपी के कहने पर ही चलेंगे।

मुंडा और बिप्लब बने पर्यवेक्षक

सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब सहित केंद्रीय भाजपा नेता बदलावों की निगरानी के लिए राज्य में हैं। बदलाव की प्रकृति स्पष्ट नहीं है, पार्टी के वरिष्ठ नेता चुप्पी साधे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में सीट-बंटवारे के समझौते पर पहुंचने में विफलता के बाद भाजपा और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जेजेपी के बीच संबंध खराब हो गए हैं। 2019 के चुनाव में भाजपा ने राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी।

हिमाचल : बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

» शीर्ष अदालत बोली- हाईकोर्ट क्यों नहीं गए

» अगली सुनवाई 18 मार्च को

नई दिल्ली। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई। मामले में अब अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच ने पूछा कि इस मामले को लेकर हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, इसमें क्या मौलिक अधिकार है, हालांकि आज अदालत ने सुनवाई टालते हुए अगली तारीख तय कर दी। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने का मामला अदालत पहुंचा है, बागी विधायकों में राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्र दत्त लखनपाल और देवेंद्र कुमार शामिल हैं।

गौरतलब हो कि राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद से ही हिमाचल प्रदेश में सियासी गहमा गहमी तेज हो गई थी। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी कैंडिडेट हर्ष महाजन के लिए क्रॉस वोटिंग की थी। इसके बाद हिमाचल सरकार खतरे में आ गई थी। राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग की थी। इसके बाद सरकार पर खतरा मंडराने लगा था। हालांकि जैसे-तैसे सुक्खू सरकार बच गई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के छह बागी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया था।

भाजपा को सत्ता से बेदखल करेगा इंडिया : अखिलेश

» सपा प्रमुख बोले- पीडीए को नजरअंदाज कर हो रहीं भर्तियां

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। कांग्रेस व सपा समन्वय समिति की बैठक के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी व मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से हटाएगा। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड लेने वालों की सूची सामने आ जाएगी। इससे पता चल जाएगा कि बॉन्ड किसने दिए हैं और किसे दिए हैं। पूछा कि यूपी में विश्वविद्यालयों में जो वाइस चांसलर नियुक्त किए गए है, उसमें से कितने पीडीए हैं। वाइस चांसलरों ने जो भर्तियां की है, उसमें कितने पीडीए है। जिलों के अधिकारियों की पोस्टिंग में कितने पीडीए हैं? बैठक के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के सभी 17 प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कराने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे। अजय राय, अराधना मिश्रा और अखिलेश यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा-कांग्रेस गठबंधन पर बनी फिल्म भी जारी की गई। कांग्रेस नेताओं के जाने के बाद अखिलेश ने पार्टी पदाधिकारियों को साझा प्रचार का महत्व समझाया।

प्रत्याशियों को जिताने में कोई कसर नहीं रखेंगे

कांग्रेस और सपा ने उन 17 सीटों पर जीत के लिए साझा रणनीति बनाई, जो इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस को दी गई हैं। सपा मुख्यालय पर सोमवार को कांग्रेस-सपा चुनाव समन्वय समिति की पहली बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता अराधना मिश्रा मोना से 17 सीटों से जुड़े सपा पदाधिकारियों का परिचय कराया गया। तय हुआ कि लोकसभा क्षेत्र स्तर पर दोनों ही दलों के नेताओं की संयुक्त बैठकें भी होंगी, ताकि प्रचार की रणनीति बन सके। समन्वय समिति की बैठक में सपा ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस इन सीटों पर किसे टिकट देती है, यह उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन, इन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सांगठनिक तैयारियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसलिए लोकसभा क्षेत्रवार दोनों दलों के नेता साझा बैठकें करके तत्काल प्रचार में जुट जाएं।

अजय राय से मिला पीड़ित परिवार

वर्तमान सरकार के हताश होकर पीड़ित शिवम दीक्षित कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से मिलने पहुंचे। शिवम् ने कहा कि बीजेपी सरकार में उनके परिवार के साथ अन्याय हुआ था और उसके घर से दो जाने चली गईं एक साथ मां बेटी की मौत हुई थी, शिवम ने कहा की अभी तक किसी भी आरोपी पर कार्यवाही नही की गई न ही सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे किए गए.। शिवम् की गुहार पर कांग्रेस नेता ने कहा कि वो शिवम की आवाज बनकर सरकार से उन्हें इंसाफ दिलाएंगे और हर प्लेटफ़ॉर्म पर उनके मुद्दों को उठाएंगे। ज्ञात हो कि कानपुर देहात में हुए मां बेटी की मौत ने पूरे प्रदेश के साथ देश को हिला दिया था इस मौत में जिले के प्रशासन और पुलिस पर इस मौत का आरोप लगा था, कि प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने अवैध अतिक्रमण के नाम पर उनकी झोपड़ी पर बुलडोजर चला दिया था। इस घटना से आहत होकर मां-बेटी झोपड़ी में चली गई थी और खुद को आग लगा ली थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। तब से पीड़ति परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है, इन लोगों ने सरकार से लेकर अधिकारियों की चौखट के चक्क र काटे लेकिन, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है।

बंगाल में उम्मीदवारों के चयन में टीएमसी की हताशा दिखती है: अधीर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोलकाता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) अंतर्कलह की वजह से बेहद हताश हो चुकी है और पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों की उसकी पसंद से यह स्पष्ट है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी ने कहा, आंतरिक कलह की वजह से टीएमसी की स्थिति दयनीय हो गई है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के दिशाहीन होने का दावा करते हुए चौधरी ने कहा कि टीएमसी को जनसभा के माध्यम से अपनी ताकत दिखानी पड़ रही है, जो एक राजनीतिक कार्यक्रम की अपेक्षा एक कॉर्पोरेट शो की तरह लग रहा है।

लोकसभा में कांग्रेस के नेता चौधरी ने कहा, टीएमसी की खराब हालात उसके उम्मीदवारों के चयन से दिखाई दे रही है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नीत वाम मोर्चा और टीएमसी घटक हैं लेकिन पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल द्वारा सभी 42 लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने से गठबंधन की उम्मीदों को गहरा झटका लगा है। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को बहरामपुर से चुनाव मैदान में उतारे जाने के सवाल पर चौधरी ने कहा कि कोई भी नागरिक देश के किसी भी हिस्से से चुनाव लड़ सकता है, जो उसका अधिकार है। पठान गुजरात के रहने वाले हैं, जिन्हें टीएमसी ने बहरामपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। चौधरी 1999 से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

अमित शाह एक बार फिर लिफ्ट में फंसेंगे: लालू

» राजद प्रमुख ने कसा तंज भाजपा बोली- उन्हें अब कोई गंभीरता से नहीं लेता

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने वर्ष 2015 में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के एक लिफ्ट में फंस जाने की घटना का जिक्र करते हुए उन पर निशाना साधा। दो दिन पहले यहां पालीगंज में आयोजित एक रैली में शाह ने राजद पर जमीन हड़पने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था और उन्हें उल्टा लटकाकर सीधा करने की बात कही थी। प्रसाद, शाह के इसी बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे।

बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए अपनी पत्नी राबड़ी देवी, पार्टी के तीन अन्य उम्मीदवारों को लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे प्रसाद ने कहा, क्या वह लिफ्ट के अंदर फंस नहीं गए थे, वह फिर फंस जाएंगे। प्रसाद का इशारा 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान की एक घटना की ओर था, जब शाह अपनी पार्टी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए पटना आए थे और यहां स्थित अतिथि गृह की एक लिफ्ट में आधे घंटे तक फंस गए थे। इस दौरान उनके साथ कई अन्य नेता भी थे। संयोग से उक्त चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगियों को हार का सामना करना पड़ा था जबकि जदयू, राजद और कांग्रेस वाले महागठबंधन ने शानदार जीत हासिल की थी। जद-यू प्रमुख नीतीश कुमार हाल ही में महागठबंधन से अलग होकर राजग में आ गए हैं। वहीं भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष एवं उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, लालू प्रसाद दशकों से राजनीति में हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा जिसे गंभीरता से लिया जा सके।

संदेह दूर करके लागू करते सीएए: मायावती

» केंद्र सरकार का कदम पीड़ित मानवता के कल्याण के लिए : योगी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। बसपा प्रमुख मायावती ने केंद्र सरकार द्वारा सीएए की अधिसूचना जारी करने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून को चुनाव से पहले लागू करने के बजाय इसके लेकर लोगों के मन में जो संदेह, असमंजस व आशंकाएं हैं, उन्हें पूरी तरह दूर करना चाहिए। इसके बाद ही इसे लागू किया जाना ही बेहतर होता। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सीएए लागू करने का केंद्र का कदम पीड़ित मानवता के कल्याण के लिए ऐतिहासिक निर्णय है।

मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान में मजहबी बर्बरता से पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मानजनक जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने मनुष्यता को आह्लादित करने वाले इस मानवीय निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का आभार जताया है। सीएम ने अधिनियम के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने जा रहे सभी लोगों का अभिनंदन किया है।

चुनावों का ध्रुवीकरण करने के लिए केंद्र का निर्णय : जयराम

वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने का केंद्र का निर्णय चुनावों का ध्रुवीकरण करने के लिए बनाया गया है। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को चार साल और तीन महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीक़े से काम करती है। सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफ़ेद झूठ की एक और झलक है। रमेश ने कहा कि नियमों की अधिसूचना के लिए नौ बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है। ऐसा स्पष्ट रूप से चुनाव को ध्रुवीकृत करने के लिए किया गया है, विशेष रूप से असम और बंगाल में। यह इलेक्टोरल बांड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख़्ती के बाद हेडलाइन को मैनेज करने का प्रयास भी प्रतीत होता है।

हम अपनी सीटों का त्याग नहीं करेंगे : उमर अब्दुल्ला

» कश्मीर में भी सीट बंटवारे को लेकर फंसा पेंच

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में इंडिया गुट में संभावित दरार देखी गई, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) नेता उमर अब्दुल्ला और पीपुल्स डेमोक्रेटक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बीच आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर बहस हो गई।। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी कठोर नहीं है और उन सीटों का बलिदान नहीं कर सकती, जो उसने पिछले चुनावों में जीती थीं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर कांग्रेस चाहे तो पीडीपी को जम्मू की सीटें दे सकती है।

हम अपनी सीटों का त्याग नहीं करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हम अड़े होते तो ममता बनर्जी की तरह सभी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित करते हैं। हम 50 प्रतिशत सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर रहे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस की जीती हुई सीट भी कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ी। हम कांग्रेस के साथ 3 सीटों पर समझौता करने को तैयार हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मचेगा सियासी बवंडर

» चुनावी बांड पर एसबीआई की फटकार से घेरे में मोदी सरकार

» विपक्ष को मिला लोस चुनाव-24 के लिए मुद्दा

» चुनाव आयोग के सहारे भी बीजपी पर वार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव-24 का बिगुल बजने वाला है उससे पहले सियासत में करवट भी होने लगी है। जहां सत्ता पर काबिज बीजेपी के शीर्ष नेता अबकी बार 400 पार का नारा लगाकर महौल बना रहे हैं उनके इस दंभ व अहंकार पर सुप्रीम कोर्ट ने करारा प्रहार किया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के सरकार के दो फैसलों में दखल देने से पूरी मोदी सरकार कटघरे में आती दिख रही है। पहले मामले में चुनावी बॉण्ड योजना के तहत किसने किस पार्टी को कितना चंदा कब-कब दिया यह बात 15 मार्च तक उजागर हो जायेगी और साथ ही दूसरे मामले में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति नए निर्वाचन आयुक्तों के नामों को तय करने के लिए 15 मार्च को जो बैठक करने वाली है उस पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं।

अभी हाल के कई निर्णयों से उच्चतम न्यायालय से मोदी सरकार को झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि एक ही दिन में सर्वोच्च न्यायालय से मोदी सरकार को दो बड़े झटके लगे हैं। एक तो न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड मामले में डाटा देने के लिए समय बढ़ाने की मांग वाली एसबीआई की याचिका खारिज कर दी। दूसरा न्यायालय उस याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जिसमें मांग की गयी है कि केंद्र सरकार को निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति नये कानून के तहत करने से रोका जाये। इस बीच चर्चा ये भी है कि अगर इन दोनों मुद्दों को विपक्ष ने जोरशोर से उठा दिया तो भाजपा के 370 के आंकड़े को करारा झटका लग सकता है।

2017 में मोदी सरकार ने शुरू की थी योजना

2017 में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रणाली के तहत लोगों और कॉर्पोरेट समूहों को चुनावी बांड नामक वित्तीय साधनों के माध्यम से गुमनाम रूप से किसी भी राजनीतिक दल को असीमित मात्रा में धन दान करने की अनुमति दी गई थी। वर्ष 2017 में वित्त विधेयक में चुनावी बांड योजना पेश की गई। 14 सितंबर, 2017 को मुख्य याचिकाकर्ता एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने योजना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 3 अक्टूबर, 2017 को स्ट ने एनजीओ द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र और ईसी को नोटिस जारी किया। 2 जनवरी, 2018 में केंद्र सरकार ने चुनावी बांड योजना को अधिसूचित किया। 7 नवंबर, 2022 को एक वर्ष में बिक्री के दिनों को 70 से बढ़ाकर 85 करने के लिए चुनावी बांड योजना में संशोधन किया गया। 16 अक्टूबर, 2023 को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एससी बेंच ने योजना के खिलाफ याचिकाओं को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा।31 अक्टूबर, 2023 को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने योजना के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। 2 नवंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा।15 फरवरी, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को रद्द करते हुए सर्वसम्मति से फैसला सुनाया और कहा कि यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ-साथ सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। 4 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक ने राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

7 मार्च को एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने 6 मार्च तक चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को किए गए योगदान का विवरण प्रस्तुत करने के शीर्ष अदालत के निर्देश की जानबूझकर अवज्ञा की।11 मार्च यानी आज उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने समय बढ़ाने की मांग करने वाली एसबीआई की याचिका खारिज कर दी और उसे 12 मार्च को कामकाजी समय समाप्त होने तक चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

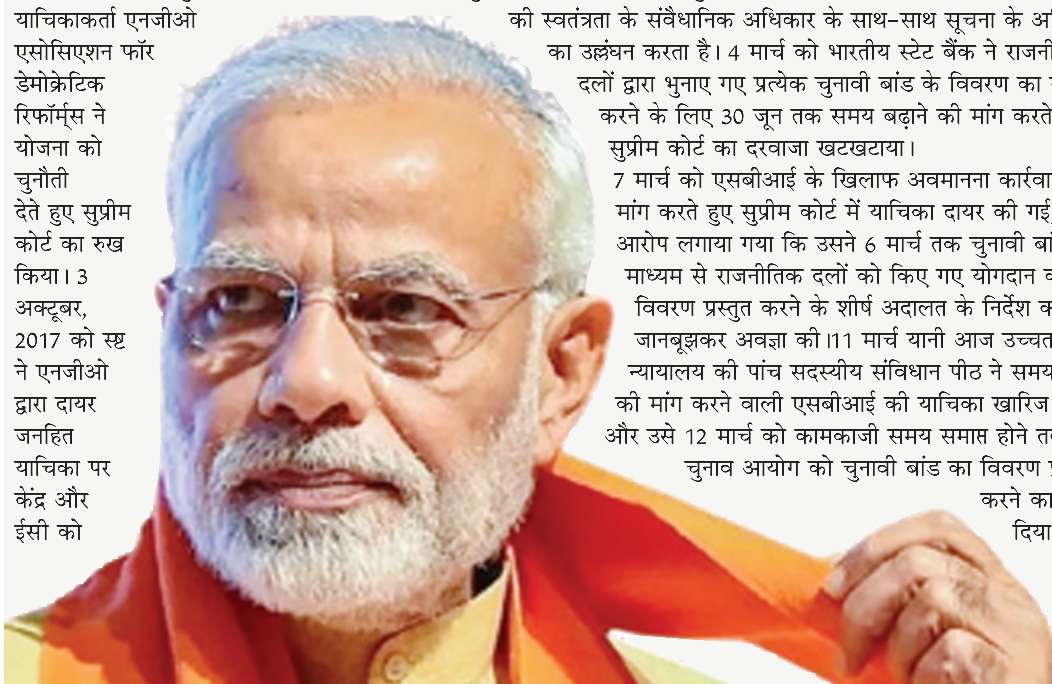

खुलेगी कई लोगों की कलई

हम आपको याद दिला दें कि पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र की चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे ''असंवैधानिक'' करार देते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और प्राप्तकर्ताओं का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने अब एसबीआई की उस याचिका पर सुनवाई की थी जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉण्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए समय-सीमा 30 जून तक बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया था। इसके अलावा, पीठ ने एक अलग याचिका पर भी सुनवाई की जिसमें एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया गया है। उधर, अदालत के फैसले के बाद याचिकाकर्ता जया ठाकुर और वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला है जोकि लोकतंत्र को मजबूत करेगा।

विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा

दूसरी ओर, अदालत के फैसले के बाद विपक्ष ने भी मोदी सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस ने चुनावी बॉण्ड का विवरण देने के लिए समय बढ़ाने की भारतीय स्टेट बैंक की मांग को हास्यास्पद करार देते हुए दावा किया कि सरकार को इस बात का डर है कि उसके सारे राज खुल जाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि उच्चतम न्यायालय एक बार फिर से भारतीय लोकतंत्र को सरकार की साजिशों से बचाने के लिए सामने आया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मामला बड़े भ्रष्टाचार का है तथा यह सरकार एवं उसके कॉरपोरेट मित्रों के बीच की सांठगांठ को भी उजागर करता है।

काले कारनामों पर पर्दा डालने की हर संभव कोशिश : खरगे

अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकाशित करने के लिए एसबीआई द्वारा साढ़े चार महीने माँगने के बाद साफ़ हो गया था कि मोदी सरकार अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने की हर संभव कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के भ्रष्टाचार, घपलों और लेन-देन की कलई खुलने की ये पहली सीढ़ी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पारदर्शिता, जवाबदेही, और लोकतंत्र में बराबरी के मौक़े की जीत है।

बैंक का डेटा छिपाने की जुगत में मोदी : राहुल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर निशाना साधा है। उन्होंने सोमवार (11 मार्च, 2024) को दावा किया कि पीएम मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है, एनडीए सरकार अपने ही बैंक का डेटा छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिर के बल खड़ी है, चंदा देने वालों पर कृपा की बौछार और जनता पर टैक्स की मार, यही है भाजपा की मोदी सरकार। केरल के वायनाड से पार्टी सांसद ने ये बातें एक्स पोस्ट के जरिए कहीं। पोस्ट के जरिए कहा गया- नरेंद्र मोदी के 'चंदे के धंधे' की पोल खुलने वाली है! 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन लाने का वायदा कर सत्ता में आई सरकार अपने ही बैंक का डेटा छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिर के बल खड़ी हो गई। राहुल गांधी के एक्स हैंडल से आगे लिखा गया- इलेक्टोरल बॉन्ड्स भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है, जो भ्रष्ट उद्योगपतियों और सरकार के नेक्सस की पोल खोल कर नरेंद्र मोदी का असली चेहरा देश के सामने लेकर आएगा। क्रोनोलॉजी स्पष्ट है- चंदा दो- धंधा लो, चंदा दो- प्रोटेक्शन लो! चंदा देने वालों पर कृपा की बौछार और आम जनता पर टैक्स की मार, यही है भाजपा की मोदी सरकार।

कोर्ट के फैसलों से बचेगा भारतीय लोकतंत्र : वेणुगोपाल

पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय एक बार फिर से भारतीय लोकतंत्र को सरकार की साजिशों से बचाने के लिए सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामला बड़े भ्रष्टाचार का है तथा यह सरकार एवं उसके कॉरपोरेट मित्रों के बीच की सांठगांठ को भी उजागर करता है। कांग्रेस ने चुनावी बॉण्ड का विवरण देने के लिए समय बढ़ाने की भारतीय स्टेट बैंक की मांग को हास्यास्पद करार देते हुए सोमवार को दावा किया कि सरकार को इस बात का डर है कि उसके सारे राज खुल जाएंगे। वेणुगोपाल ने एक्स पर पोस्ट किया, उच्चतम न्यायालय एक बार फिर भारतीय लोकतंत्र को इस शासन की कुटिल साजिशों से बचाने के लिए आगे आया है। उन्होंने दावा किया, एसबीआई द्वारा एक दिन के साधारण से काम के लिए समय बढ़ाने की मांग करना हास्यास्पद था। सच तो यह है कि सरकार को डर है कि उनके सारे राज़ सामने आ जायेंगे। वेणुगोपाल का कहना था, उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रमाणित यह महाभ्रष्टाचार का मामला, भाजपा और उसके भ्रष्ट कॉरपोरेट मित्रों के बीच अपवित्र सांठगांठ को उजागर करेगा। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट किया, जो सत्ता में आए थे स्विस बैंकों के खातों को सार्वजनिक करने की बातें करके वो आज एसबीआई तक के आंकड़ों को सार्वजनिक करने में थर-थर कांप रहे हैं।

निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर भी उठे सवाल

जहां तक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति वाली बात है तो आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह केंद्र सरकार को 2023 के एक कानून के अनुसार नए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करने से रोकने का अनुरोध करने वाली यचिका को सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा। इस कानून के प्रावधानों को पहले ही न्यायालय में चुनौती दी गयी है। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे और अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों के दो पद खाली हो गए हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, ''एक ईमेल भेजिए। हम देखेंगे।'' कांग्रेस नेता जया ठाकुर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह और अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए पेश किया। स्थानीय कांग्रेस नेता ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को चुनौती दी है। ठाकुर ने अपनी याचिका में न्यायालय को बताया कि उनकी याचिका पर सुनवाई लंबित रहने के दौरान 'निर्वाचन आयोग के एक सदस्य अरुण गोयल ने नौ मार्च 2024 को इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है।' उन्होंने कहा कि उनकी याचिका पर 12 जनवरी को एक नोटिस जारी किया गया था। हम आपको बता दें कि निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल ने 2024 के लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से कुछ दिन पहले शुक्रवार सुबह पद से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया और केंद्रीय विधि मंत्रालय ने इसकी घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी की। इससे निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार इकलौते सदस्य रह गए हैं। इसके चलते प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति नए निर्वाचन आयुक्तों के नामों को तय करने के लिए 15 मार्च को बैठक करेगी।

जिद... सच की

Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma

@Editor_Sanjay

सिर्फ चौड़ी सड़कें व मेट्रो से नहीं होता विकास

"वकासशील देशों को विकसित राष्ट्रों में बदलने की चुनौती को समझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल होने वाला एक टर्म है- डेनमार्क पहुंचना। इसमें असल में उस खूबसूरत और समृद्ध देश तक पहुंचने की बात नहीं है, बल्कि समृद्ध, लोकतांत्रिक, सुरक्षित, बेहतर शासन और कम भ्रष्टाचार वाले समाज की कल्पना करना है। क्या शामिल है? बेशक, एक देश को अमीर होना चाहिए, लेकिन सिर्फ पैसा ही काफी नहीं है।

भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो सिर्फ आर्थिक समृद्धि काफी नहीं होगी बल्कि उसे कुछ और रास्ते अपनाने होंगे । एक विकसित देश के कई अनिवार्य पहलू हैं जिनमें किसी एक को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पीएम मोदी बार-बार अपने भाषणों में भारत को विक सिशील से विकसित देश बनाने की बात करते हैं। परंतु क्या सिर्फ चौड़ी सड़कें, मेट्रो व ऊंची इमारतें ही विकास का पैमाना हैं, या कुछ और भी। रिजर्व बैंक से जुड़े रहे विशेषज्ञों का कहना कि कानून का राज, जवाबदेह सरकार व सामाजिक समरसता व आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार से ही कोई देश विकसित राष्ट्र बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा सपना है कि भारत 2047 में अपनी आजादी के 100 साल पूरे होने तक एक विकसित राष्ट्र बन जाए। नीति आयोग इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रोडमैप बनाने में लगा हुआ है। विकासशील देशों को विकसित राष्ट्रों में बदलने की चुनौती को समझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल होने वाला एक टर्म है- डेनमार्क पहुंचना। इसमें असल में उस खूबसूरत और समृद्ध देश तक पहुंचने की बात नहीं है, बल्कि समृद्ध, लोकतांत्रिक, सुरक्षित, बेहतर शासन और कम भ्रष्टाचार वाले समाज की कल्पना करना है। क्या शामिल है? बेशक, एक देश को अमीर होना चाहिए, लेकिन सिर्फ पैसा ही काफी नहीं है। लोगों को बेहतर जीवन स्तर का आनंद लेने की भी जरूरत है। इसके लिए समाज को नियमों, एक मजबूत राज्य और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर टिका होना चाहिए। कानून हर किसी पर समान रूप से लागू होता है। इसका मतलब है कि जो कोई भी कानून तोड़ता है, चाहे वह कितना भी ताकतवर या प्रभावशाली क्यों न हो, उसे पकड़ा जाएगा और दंडित किया जाएगा। इसका मतलब यह भी है कि जनता को सरकार के अत्याचार से बचाया जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा कि थॉमस जेफरसन ने अमेरिकी संविधान बनाते समय कहा था-सरकारें अपूर्ण लोगों से बनी होती हैं, जो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। कानून का राज उस पर लगाम लगाने का काम करता है। कानून का राज अकेले काम नहीं करता, उसके साथ एक मजबूत राज्य की भी जरूरत होती है। एक मजबूत राज्य का मतलब तानाशाह शासन नहीं, बल्कि ऐसा राज्य है जो जनता के भले के लिए कड़े नियम बनाता है और उनका पालन करवाता है। साथ ही, वह सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं और लैंगिक समानता, वित्तीय समावेशन जैसी विकासोन्मुखी सुविधाएं भी प्रदान करता है। जनता के भले के लिए काम करने वाला एक मजबूत राज्य भी हमें डेनमार्क तक नहीं पहुंचा सकता, अगर सरकार जवाबदेह नहीं है।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

मालदीव में पाकिस्तानी खेल समझना भी जरूरी

पुष्परंजन

बाईस फरवरी, 2010 की बात है, मालदीव के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद वहीद हसन ने अपने दिल्ली आगमन के दौरान भारतीय मीडिया को बताया कि मालदीव के युवाओं को पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आतंकवादी समूहों द्वारा जिहाद के लिए भर्ती किया जा रहा है। डॉ. मोहम्मद वहीद हसन ने संकेत दिया कि लश्कर-ए-तैयबा, जिसे नवंबर, 2008 में मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार माना जाता है, मालदीव में सक्रिय था। उस समय भारतीय खुफिया ब्यूरो के सूत्रों के हवाले से बताया कि पाक समर्थित समूह के लगभग लगभग एक हजार कार्यकर्ता मालदीव में सक्रिय थे।

वहीद ने कट्टरपंथी संस्थानों में भाग लेने वाले संदिग्ध युवाओं को वाया भारत आने से रोकने के लिए सहायता मांगी थी। तत्कालीन उपराष्ट्रपति के प्रेस सचिव मोहम्मद जुहैर ने तब कहा था कि पाकिस्तान में 200 से 300 अपंजीकृत मालदीवियन छात्र हैं। ऐसे कई संदिग्ध वाया कोलंबो या कोच्चि मालदीव में एंट्री लेते हैं। तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद वहीद हसन ने जो कुछ फरवरी, 2010 में कहा था, वो बात आई-गई हो गई। न तो पाकिस्तान का शासन जिहादियों को तैयार करने से रोक सका, और भारत तो बस मूकदर्शक की भूमिका में था।

मालदीव-पाकिस्तान के संबंधों को समझना है तो वहां की संसद को देखिये, जिसका निर्माण पाकिस्तान ने 45 मिलियन रुपये लगाकर किया था। माले के मागू स्थित पार्लियामेंट 'मजलिस' का उद्घाटन 1 अगस्त, 1998 को पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की उपस्थिति में किया गया था। उसके 19 साल बाद, 25 जून, 2017 को मालदीव के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी पत्नी कलसूम नवाज शरीफ को आमंत्रित किया था। नवाज को दोबारा मालदीव बुलाने से पहले तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन 7 मई, 2015 को इस्लामाबाद भी गये थे। देखते-देखते मालदीव, पाकिस्तान का हम प्याला-हम निवाला बन गया। राष्ट्रपति यामीन ने जिन देशों में अपने दूत भेजे, उनमें पाकिस्तान भी शामिल था। पाक सेना के तत्कालीन प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने मार्च, 2018 के अंत में मालदीव का दौरा किया था। इस समय पाकिस्तान में मालदीव के अधिकांश छात्र देशभर के विभिन्न

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में डिग्री और पाठ्यक्रम कर रहे हैं। स्थानीय दूतावास और मालदीव सरकार के रिकॉर्ड के आधार पर पंजीकरण के अनुसार, उनकी संख्या सैकड़ों में है, जो 400 से 600 अपंजीकृत तालिब मदरसों में दीक्षा ले रहे हैं, वो पूरे उपमहाद्वीप के लिए खतरनाक हो सकते हैं।

1965 में मालदीव एक स्वतंत्र देश बना। भारत इस द्वीपीय राष्ट्र को मान्यता देने वाला पहला देश था। 1972 में भारत ने मालदीव में अपना पहला उच्चायोग स्थापित किया, जबकि 2004 में मालदीव ने नई दिल्ली में अपना पहला पूर्ण राजनयिक मिशन खोला था। ठीक से देखा जाए तो भारत ने दो दशकों में मालदीव से उतार-चढ़ाव वाले कूटनीतिक संबंध बनाये रखा। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि चीन पर दोष मढ़ने की बजाय, भारत को अपने पड़ोसी देशों में चल रही गतिविधियों को ध्यान में रखकर दूरगामी रणनीति बनाने की जरूरत थी। आप मानें न मानें पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब और तुर्की का नेक्सस की भूमिका दिल्ली से माले के संबंध बिगाड़ने में दरपेश रही है।

बात भी सही है। भारत क्या पड़ोस से खुफिया जानकारी जुटाने में पीछे रहा है? या उसके एक्शन प्लान में कोई खोट है? इन सवालों का बेहतर उत्तर विदेश मंत्रालय ही दे सकता। चीन-मालदीव मैत्री पुल मालूम नहीं दिल्ली को कब दिखा। मालदीव की राजधानी माले को हुलहुले द्वीप से जोड़ने वाले पुल, 'क्रॉस-सी ब्रिज', का उद्घाटन 30 अगस्त, 2018 को किया गया था। जब यह पुल बना, उन दिनों मुइज्जू माले के मेयर थे। बताते हैं कि उसी कालखंड में चीनी राजदूत से उनकी नजदीकियां बढ़ी थीं। यह चीन की वन बेल्ट रोड इनीशिएटिव की शुरुआत थी, मगर अफसोस नई दिल्ली चीनी कूटनीति की रफ्तार को समझ नहीं पाया। पाकिस्तान द्वारा निर्मित मालदीव की संसद और चीन द्वारा निर्मित एक ऐसा पुल, जो माले को हुलहुले द्वीप से जोड़कर वहां की साढ़े चार लाख की आबादी में छवि निर्माण कर रहा था। बावजूद इस खबर के, हम 2024 तक लगभग सोये रहे।

18 मई, 2023 को भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मालदीव की तीन दिवसीय यात्रा पर थे। यात्रा के दौरान मालदीव रक्षा बल (एमएनडीएफ) को एक फास्ट पेट्रोल जहाज और एक लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट जहाज सौंपा। उथुरु थिला फाल्हू में एकथा हार्बर के निर्माण की आधारशिला रखी। तब राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत और मालदीव के बढ़ते रक्षा सहयोग को हम और सुदृढ़ करेंगे।

पेड़ों के बिना बेमानी है वन्यजीव संरक्षण का दावा

ज्ञानेन्द्र रावत

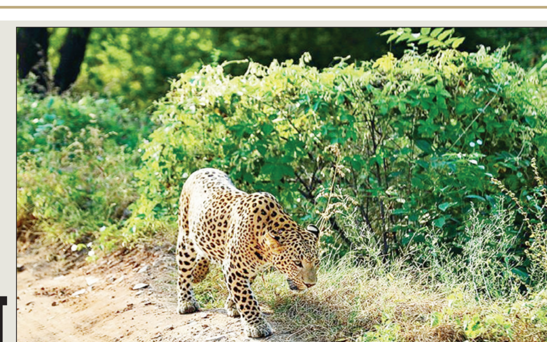

बीते कुछ महीनों से जंगलों और पेड़ों की अवैध कटाई का मसला विशेष रूप से चर्चा में है। इस मसले पर देश की सुप्रीम अदालत काफी गंभीर है और उसने संज्ञान लेना शुरू भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्बेट रिजर्व नेशनल पार्क में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई को अनुमति देने के लिए उत्तराखंड सरकार के पूर्व वन मंत्री और पूर्व प्रभागीय वन अधिकारी की खिंचाई की व फटकार लगाई।

सरकार देश में राष्ट्रीय पशु बाघ की संख्या में बढ़ोतरी का दावा करते नहीं थकती। एक समय विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके बाघों की तादाद में बढ़ोतरी वास्तव में प्रशंसा का विषय तो है ही, गर्व का विषय भी है। हाल ही में जारी केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट में तेंदुओं की तादाद में बढ़ोतरी का दावा किया गया है, और कहा गया है कि यह देश में जैव विविधता के प्रति भारत के अटूट समर्पण का प्रमाण भी है। अब तेंदुओं की संख्या बढ़कर करीब 13,874 हो गयी है। सरकार की उस घोषणा का भी स्वागत किया जाना चाहिए जिसके तहत सरकार ने वन्यजीवों की सात प्रजातियों यथा बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीते के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस बनाया है। इसकी सफलता उसी दशा में संभव है जब देश-दुनिया में वन्य जीवों के लिए न केवल उनके अनुकूल वातावरण हो, और साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। यहां इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि वन्य जीव और वन्य जीवन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बेहद महत्वपूर्ण है।

जनसंख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी, अनियंत्रित औद्योगिक विकास और शहरीकरण के कारण जहां जंगलों की बेतहाशा कटाई के चलते वन्यजीवों के आवास लगातार खत्म किये जा रहे हैं, वहीं वन्य जीवों के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया है। यही अहम कारण हैं कि वन्यजीव भोजन की तलाश में अब मानव बस्तियों की ओर रुख करने लगे हैं। इसका दुष्परिणाम वन्यजीव-मानव संघर्ष के रूप में सामने आया है। इस संघर्ष को टालने का एकमात्र समाधान है जंगलों की कटाई पर रोक लगाना। इस पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा कि यह संकट कुछेक वन्य जीवों का ही सवाल नहीं है, बल्कि दूसरी प्रजातियों के अस्तित्व से भी जुड़ा है। उस दशा में उन दूसरी प्रजातियों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में पारिस्थितिकीय संतुलन का बिगाड़ अवश्यंभावी है। बीते कुछ महीनों से जंगलों और पेड़ों की अवैध कटाई का मसला विशेष रूप से चर्चा में है। इस मसले पर देश की सुप्रीम अदालत काफी गंभीर है और उसने संज्ञान लेना शुरू भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्बेट रिजर्व नेशनल पार्क में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई को अनुमति देने के लिए उत्तराखंड सरकार के पूर्व वन मंत्री और पूर्व प्रभागीय वन अधिकारी की खिंचाई की व फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई इस प्रकरण की पहले ही जो जांच कर रही है, वह तीन महीने में इसकी जांच रिपोर्ट अदालत में पेश करे। पीठ ने कहा कि राज्य सरकार को भविष्य में ऐसे कारनामें रोके व पहले हो चुके नुकसान की भरपायी के लिए तत्काल कदम उठाए।

दरअसल पेड़ों की कटाई जैसे मसले पर देश की सुप्रीम अदालत की यह टिप्पणी एक सबक है। उसने कहा है कि वैधानिक प्रावधानों को ताक पर रखने जैसे पूर्व वन मंत्री और वन अधिकारी के दुस्साहस आश्चर्यचकित करने वाले हैं। यह विडंबना है कि वन अधिकारी पर गंभीर आरोप होने के बावजूद तत्कालीन वन मंत्री ने नियमों की अनदेखी कर उन्हें डीएफओ नियुक्त कर दिया। यह पूरा मामला राजनेता, नौकरशाहों की मिलीभगत का ज्वलंत उदाहरण है। गौरतलब है कि कोर्ट की केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने पहले सीटीआर के कालागढ़ वन प्रभाग के पाखरो और मोरघट्टी वन क्षेत्रों में 2021 में बाघ सफारी के संबंध में निर्माण सहित विभिन्न अवैध गतिविधियों के लिए पूर्व मंत्री और वनाधिकारी को जिम्मेदार ठहराया था। दरअसल, यह मामला अधिवक्ता और पर्यावरण कार्यकर्ता द्वारा दायर याचिका के चलते उजागर हुआ जिसमें पाखरो टाइगर सफारी में अवैध निर्माण के साथ-साथ अवैध रूप से हजारों पेड़ों की कटाई का आरोप लगाया था। पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर देश में यह पहला मामला है जिसमें किसी मंत्री की संलिप्तता का खुलासा हुआ है और देश की सर्वोच्च अदालत ने संज्ञान लेते हुए गंभीर टिप्पणी करते हुए जिम्मेदार व्यक्तियों से नुकसान की भरपायी करने तथा राज्य के दोषी अधिकारियों के खिलाफ छह माह में अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया है। उस हालत में जबकि देश में विकास के नाम पर, औद्योगिक कारखानों, एक्सप्रेस-वे या आल वैदर रोड के नाम पर या फिर पर्यटन के नाम पर पेड़ों को, जंगलों को विकास प्रक्रिया की भेंट चढ़ाया जाता है और इनके खिलाफ जनता द्वारा किये जा रहे धरने, विरोध प्रदर्शन और जन आंदोलन सब के सब बेमानी हो गये हैं।

अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का परिणाम भविष्य में क्या होगा। यदि यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो देश एक दिन हरित संपदाविहीन भी हो सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन की दशा में वन्य जीव संरक्षण के दावे बेमानी हो जायेंगे। पेड़ों के बिना लोग ऑक्सीजन के अभाव में अकाल मौत के मुंह में जाने को विवश होंगे। कोरोना काल के भयावह मंजर से भी यदि देश के नीति-नियंताओं ने सबक नहीं सीखा, तो उस दशा में क्या होगा, यह किसी से छिपा भी नहीं है।

शिमला और मनाली

जाएं नए कपल

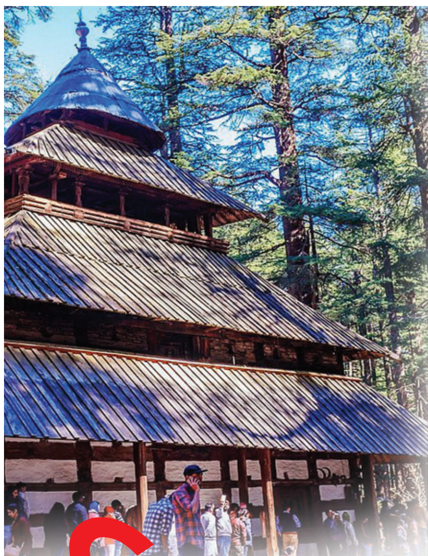

हिडिम्बा देवी मंदिर

पुरानी मनाली में हिडिंबा देवी मंदिर है जो पर्यटकों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। इसे घूमने के लिए 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है। इस पगोड़ा स्टाइल मंदिर को लकड़ी से तैयार किया गया है। इसके आसपास का नजारा देखते ही बनता है। आसपास मनु मंदिर, मां शरवारी मंदिर, तिब्बत मोनेस्ट्री भी स्थित हैं।

जोगिनी झरना

वशिष्ठ रोड पर स्थित जोगिनी झरना मनाली से 2.8 किमी की दूरी पर है। देवी जोगिनी गांव और शक्तिपीठ के मशहूर ये स्थान कपल के प्यारा अनुभव कराता है।

ट्री हाउस

कुल्लू मनाली घाटी हरियाली से घिरा है, जहां कपल हनीमून के दौरान ट्री हाउस में रह सकते हैं और भीड़ से दूर शांत जगह से हरे-भरे जगह में एक दूसरे के साथ वक्त बिता सकते हैं। ट्री हाउस आपको केटेन में मिल जाएंगे। अपने हमसफर का हाथ थाम कर या उनकी बाहों में समाते हुए पहाड़ों से सूर्योदय या सूर्यास्त का नजारा देखना बहुत ही रोमांटिक अनुभव करा सकता है। मनाली इस तरह का अनुभव भी ऑफर करता है।

सोलांग वैली

मनाली से 14 किमी दूर सोलांग वैली है, जहां पहुंचने के लिए 3 से 4 घंटे का वक्त लगता है। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठा सकते हैं। यहां पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, पैरासूटिंग, हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। यह वैली पैराग्लाइडिंग के लिए भारत की बेस्ट जगहों में से एक है।

हाल ही में शादी हुई है और हनीमून पर जाने की योजना बना रहे हैं तो इस मौसम में भारत की कुछ जगहें पर जाना बेस्ट विकल्प है। हालांकि हनीमून की योजना बनाने के दौरान अपने समय और बजट के अनुरूप ही जगह का चयन करें। शादी के लिए युगल लंबी छुट्टियां ले चुका होता है, ऐसे में हनीमून पर जाने के लिए अगर आपको दफ्तर से अधिक दिनों की छुट्टी नहीं मिल रही है या शादी के खर्च के बोझ से परेशान हैं और बजट भी ज्यादा नहीं है तो ऐसी जगहों का चयन कर सकते हैं, जहां कम दिनों में अधिक एन्जॉय कर सकते है, वो भी बजट में। हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन हनीमून पर जाने के लिए परफेक्ट रहेंगे। हिमाचल के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में शिमला और मनाली का नाम आता है। बहुत अधिक भीड़भाड़ से दूर शांत माहौल में अपनी जीवनसाथी के साथ प्यार भरा वक्त बिताने के लिए मनाली जा सकते हैं। मनाली जाने से पहले कपल पूरी जानकारी इकट्ठा कर लें, कि कैसे अपने शहर से मनाली का सफर कर सकते हैं। मनाली जाने के लिए कितना खर्च आएगा, मनाली में क्या और कहां जा सकते हैं और कैसे कपल एन्जॉय कर सकते हैं।

भृगु झील

मनाली से 22 किमी दूर कुल्लु में स्थित भृगु झील तक पहुंचने में 2-3 घंटे का समय लगता है। यहां महर्षि भृगु ने ध्यान लगाया था। यहां से कपल कैंपिंग के लिए भी जा सकते हैं और रास्ते में स्टॉबेरी के बागान देख सकते हैं।

हंसना मना है

टीचर: बताओ सबसे नशीला पदार्थ कौन सा होता है? पप्पु: किताब है सर, साला खोलते ही नींद आ जाती है।

बच्चा मेडीकल वाले से: अंकल, गोरा करने वाली कोई क्रीम है? मेडिकल वाला: हां है.. शरारती बच्चा: तो साले, लगाता क्यों नहीं? रोज तेरा मुंह देखकर डर जाता हूं!

डॉक्टर: पप्पु अब तुम्हारी पत्नी कैसी है? पप्पु: अब काफी सुधार है उसकी तबियत में, आज सुबह तो थोड़ी बहुत लड़ाई भी की उसने।

2 हफ्तों से ज्यादा खासी टीबी बन जाती है.. अगर टाइम पे गर्लफ्रेंड ना चेंज करो तो वो बीबी बन जाती है।

गर्लफ्रेंड: मेरी याद आती है तो तुम क्या करते हो? बॉयफ्रेंड: तुम्हारी पसंदीदा चाकलेट खा लेता हूं। और तुम क्या करती हो मेरी याद आये तब, गर्लफ्रेंड: मैं भी 'विमल' खा लेती हूं।

मेरे हिसाब से दुनिया में, सतर्क इन्सान वही है, जो इन्सान टॉयलेट में बैठने से पहले, पानी का नल चला कर देख ले, की पानी आ रहा है की नहीं।

कहानी — मूर्ख बगुला और नेवला

कई सालों पहले की बात है, एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर एक बगुला रहा करता था। उसी पेड़ के नीचे एक बिल में एक सांप भी रहता था। वह सांप बड़ा ही दुष्ट था। अपनी भूख मिटाने के लिए वह बगुले के छोटे-छोटे बच्चों को खा जाया करता था। इस बात से बेचारा बगुला बहुत परेशान था। एक दिन की बात है, सांप की हरकतों से परेशान होकर बगुला नदी के किनारे जाकर बैठ गया। बैठे-बैठे अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। बगुले को रोता देख नदी में से एक केकड़ा बाहर आया और बोला, अरे बगुला भैया, क्या बात है? यहां बैठे-बैठे आंसू क्यों बहा रहे हो? क्या परेशानी है? केकड़े की बात सुनकर बगुला बोला, क्या बताऊं केकड़े भाई, मैं तो उस सांप से परेशान हो गया हूं। वह बार-बार मेरे बच्चों को खा जाता है। घोंसला चाहे जितना भी ऊपर बनाऊं, वह ऊपर चढ़ ही जाता है। अब तो उसके कारण दाना पानी लेने के लिए घर से कहीं जाना भी मुश्किल हो गया है। तुम ही कोई उपाय बताओ। बगुले की बात सुनकर केकड़े ने सोचा कि बगुला भी तो अपना पेट भरने के लिए उसके परिवार वालों और दोस्तों को खा जाता है। क्यों न ऐसा कोई उपाय किया जाए कि सांप के साथ साथ बगुले का भी खेल खत्म हो जाए। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने बगुले से कहा, एक काम करो बगुला भैया। तुम्हारे पेड़ से कुछ ही दूर नेवले का बिल है। तुम सांप के बिल से लेकर नेवले के बिल तक मांस के टुकड़े बिछा दो। नेवला जब मांस खाते हुए सांप के बिल तक आएगा तो वह सांप को भी मार देगा। बगुले को यह उपाय सही लगा और उसने ठीक वैसा ही किया जैसा केकड़े ने कहा, लेकिन इसका परिणाम उसे भी भुगतना पड़ा। मांस के टुकड़े खाते-खाते जब नेवला पेड़ के पास आया तो उसने सांप के साथ बगुले को भी अपना शिकार बना लिया।

7 अंतर खोजें

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष

बिगड़े काम बनेंगे। निवेश मनोनुकूल लाभ देगा। नौकरी में प्रभाव वृद्धि होगी। कोई पुराना रोग बाधा का कारण हो सकता है। सामाजिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा।

वृषभ

धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है। सत्संग का लाभ मिलेगा। राजकीय सहयोग प्राप्त होगा। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। नौकरी में सहकर्मी साथ देंगे।

मिथुन

वाहन, मशीनरी व अग्नि के प्रयोग में सावधानी रखें। विशेषकर गृहिणियां लापरवाही न करें। आवश्यक वस्तुएं गुम हो सकती हैं। दुष्जन हानि पहुंचा सकते हैं।

कर्क

वाणी में शब्दों का प्रयोग सोच-समझकर करें। प्रतिद्वंद्विता में कमी होगी। राजकीय सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है। व्यापार में वृद्धि होगी।

सिंह

स्थायी संपत्ति के बड़े सौदे बड़ा लाभ दे सकते हैं। मनपसंद रोजगार मिलेगा। आर्थिक उन्नति के प्रयास सफल रहेंगे। कर्ज समय पर चुका पाएंगे। बैंक-बैलेंस बढ़ेगा।

कन्या

किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठा पाएंगे। यात्रा लाभदायक रहेगी। बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे। लेन-देन में सावधानी रखें।

तुला

आय में निश्चितता रहेगी। शत्रु शांत रहेंगे। व्यापार-व्यवसाय से लाभ होगा। बुरी खबर मिल सकती है, धैर्य रखें। दौड़धूप की अधिकता का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा।

वृश्चिक

आवश्यक वस्तु समय पर नहीं मिलने से खिन्नता रहेगी। बनते कामों में बाधा उत्पन्न होगी। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। काम में मन नहीं लगेगा।

धनु

जल्दबाजी व लापरवाही से हानि होगी। राजकीय कोप भुगतना पड़ सकता है। विवाद न करें। शुभ समाचार प्राप्त होंगे। प्रसन्नता रहेगी। बिछड़े मित्र व संबंधी मिलेंगे।

मकर

व्यावसायिक यात्रा लाभदायक रहेगी। रोजगार मिलेगा। आय में वृद्धि होगी। कारोबार में वृद्धि होगी। शेयर मार्केट मनोनुकूल लाभ देगा। बुद्धि का प्रयोग करें।

कुम्भ

आंखों का विशेष ध्यान रखें। चोट व रोग से बचाएं। पुराना रोग उभर सकता है। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। वाणी पर नियंत्रण रखें। व्यवसाय की गति धीमी रहेगी।

मीन

यात्रा मनोनुकूल रहेगी। कारोबार से संतुष्टि रहेगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। प्रयास सफल रहेंगे। बुद्धि का प्रयोग करें। प्रमाद न करें। निवेश से लाभ होगा।

बॉलीवुड | मन की बात

ऐ वतन मेरे वतन में इमरान लोहिया के रोल में आएंगे नजर

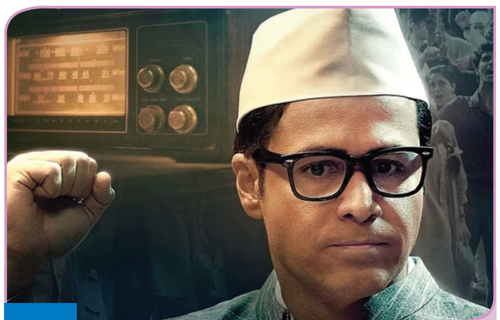

कन्नन अय्यर के निर्देशन में बनी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म ऐ वतन मेरे वतन की रिलीज की तारीख से पर्दा उठ गया है। दरब फारूकी और अय्यर द्वारा लिखित इस फिल्म में सारा अली खान मुख्य भूमिका में हैं। वहीं, इमरान हाशमी विशेष कैमियो में नजर आने वाले हैं। इमरान हाशमी आगामी देशभक्ति थ्रिलर ऐ वतन मेरे वतन में राम मनोहर लोहिया का किरदार निभाने के लिए तैयार हैं। अब हाल ही में, अभिनेता का फिल्म से नया पोस्टर जारी हुआ है। बहुप्रतीक्षित देशभक्ति फिल्म ऐ वतन मेरे वतन इस महीने रिलीज के लिए तैयार है। सारा अली खान की इस फिल्म में इमरान हाशमी राम मनोहर लोहिया के किरदार में कैमियो रोल करते नजर आएंगे। अब फिल्म के नए पोस्टर ने फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है। इमरान का यह लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है। वही, इमरान भी भूमिका में फिट बैठते नजर आ रहे हैं।
प्राइम वीडियो ने पोस्टर साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, स्वतंत्रता की निडर आवाज को प्रसारित करना! यह इमरान के इस ऐतिहासिक चरित्र के चित्रण की एक आकर्षक झलक पेश करता है। फिल्म में अपने किरदार के बारे में बात करते हुए इमरान ने कहा उन्होंने पहले कभी भी फीडम फाइटर की भूमिका नहीं निभाई है। खुद को राम मनोहर लोहिया के किरदार में ढालना उनके लिए सम्मान की बात है। फिल्म के बारे में बात करते हुए इमरान हाशमी ने कहा कि इस तरह की कहानी का हिस्सा बनना उनके लिए सौभाग्य की बात है।
सारा अली खान और इमरान हाशमी के अलावा, ऐ वतन मेरे वतन के कलाकारों में सचिन खेडेकर, अभय वर्मा, स्पर्श श्रीवास्तव, एलेक्स ओ नील और आनंद तिवारी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज ना होकर सीधे ओटीटी प्लेटफार्म प्राइम वीडियो पर 21 मार्च 2024 को रिलीज हो रही है।

किलियन मर्फी के ऑस्कर जीतने से खुश हैं यामी गौतम, बोलीं- आपकी प्रतिभा किसी भी चीज से ऊपर है

ऑस्कर 2024 में किलियन मर्फी की धूम देखने को मिली है। अभिनेता ने ओपेनहाइमर में अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली परफॉर्मेंस के लिए ऑस्कर में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीत लिया है। मर्फी ने एक साइंटिस्ट के रोल में ऐसा जादू फूंका कि पब्लिक देखती ही रह गई। केवल पब्लिक ही नहीं क्रिटिक्स भी हैरान रह गए। अब यामी गौतम ने किलियन मर्फी की प्रशंसा की है और उनके लिए एक नोट साझा कर बधाई दी है। यामी ने एक नोट साझा कर लिखा, पिछले कुछ वर्षों से किसी भी मौजूदा नकली फिल्मी पुरस्कारों पर कोई विश्वास नहीं होने के कारण मैंने उनमें भाग लेना बंद कर दिया है, लेकिन आज मैं एक उम्दा कलाकार के लिए बहुत में खुश महसूस कर रही हूं, जिसने अपने धैर्य, अभिनय और अच्छाई से सभी को अपना फैन बना लिया है। सबसे बड़े वैश्विक मंच पर उन्हें सम्मानित होते देखना हमें बताता है कि अंत में यह आपकी प्रतिभा है जो किसी भी चीज से ऊपर है। जैसे ही यामी ने नोट पोस्ट किया, प्रशंसकों ने उनके कमेंट बॉक्स में तारीफों की बाढ़ ला दी। एक यूजर ने कमेंट किया, क्वीन। दूसरे यूजर ने लिखा है, बहुत आगे बढ़ें। जब किसी डिजर्विंग कलाकार को पुरस्कार मिलता है तो सभी काफी सम्मानित महसूस करते हैं। एक और यूजर ने लिखा, सिलियन मर्फी यह अवॉर्ड पूरी तरह से डिजर्व करते थे। उन्हें अवॉर्ड लेता देख बहुत खुशी हो रही है। किलियन मर्फी ने क्रिस्टोफर नोलन निर्देशित ओपेनहाइमर में अपने बेहतरीन अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीता। वह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले पहले आयरिश मूल के स्टार हैं। इस बार ऑस्कर ओपेनहाइमर के नाम रही, क्योंकि इसने सर्वश्रेष्ठ चित्र और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित कार्यक्रम के सात बड़े पुरस्कार अपने नाम कर लिए। वहीं, बात करें फिल्म की तो आर्टिकल 370 में यामी गौतम ने जूनी हक्सर नाम की एनआईए एजेंट की भूमिका निभाई है, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया और अब यह बॉक्स ऑफिस पर सफलतापूर्वक अपना प्रदर्शन कर रही है।

ओटीटी प्लेटफॉर्म से कुछ नया करना चाहता हूं: सनी देओल

अभिनेता सनी देओल इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। साल 2023 की सबसे बड़ी हिट गदर 2 की सफलता के बाद अब अभिनेता अपनी अगली फिल्म की तैयारी में जुट गए हैं। सनी राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनने वाली फिल्म लाहौर 1947 में अहम भूमिका निभाते दिखाई देंगे। हाल ही में अभिनेता अपनी आने वाली फिल्म के अलावा अपने ओटीटी डेब्यू पर भी मीडिया से खुलकर बातें करते नजर आए। साल 2023 में सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड को ध्वस्त किया था। इस फिल्म में वे अमीषा पटेल के साथ दिखाई दिए थे। हाल ही में अभिनेता ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, मैं फिल्मों के अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी काम करने के लिए तैयार हूं। मुझे वेब सीरीज में काम करने से कोई परेशानी नहीं है। अगर मुझे अलग और नया विषय मिले तो मैं जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपको दिखूंगा। सनी अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं,

बॉलीवुड | मसाला

साल 2025 मेरे लिए एक दिलचस्प साल होने वाला है। इस साल मेरी फिल्में मेरे करियर का दिशा तय करने वाली हैं। मैं चाहता हूं कि नई पीढ़ी के दर्शक भी मेरे काम को देखे और सराहे। मैं अब उन विषयों पर काम करना चाहता हूं जिन पर फिल्में नहीं बन सकती हैं। मैं वैसी वेब सीरीज में काम करना चाहता हूं जो मेरी फिल्मों से अलग हों। मेरा चाहता हूं जब दर्शक मुझे ओटीटी पर देखें तब उन्हें लगे कि मैंने कुछ बढ़िया और नया किया है। सनी देओल इन दिनों आमिर खान के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म लाहौर 1947 की शूटिंग में व्यस्त हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म में वे अपने पिता धर्मेंद्र और बेटे करण देओल के साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में वे पहली बार शबाना आजमी के साथ भी काम करते दिखाई देंगे। वहीं, सूत्रों की मानें तो सनी देओल फिल्म सफर और बॉर्डर के सीक्वल में भी अपने अभिनय का जलवा बिखरते नजर आने वाले हैं।

अजब-गजब | ज्वालामुखी के पास रहते हैं ये जानवर

अलग ही माहौल में रहने की है काबिलियत

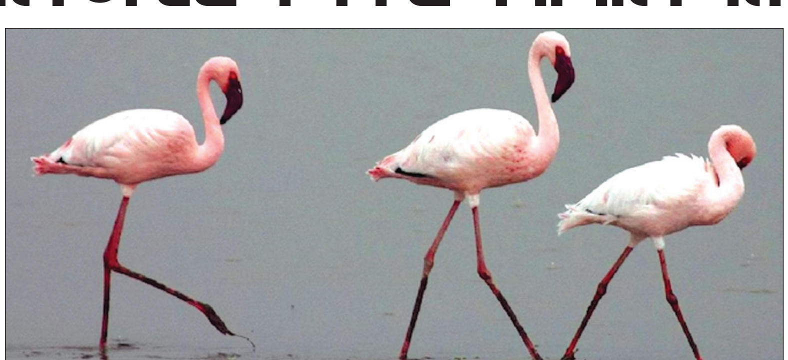

दुनिया में ज्वालामुखी के पास की जगह ऐसी होती हैं, जहां पर जीवन के लिए माहौल बहुत ही अलग होता है। यहां पर पाए जाने वाले जानवर कुछ अलग ही तरह के होते हैं। इनकी क्षमताएं और भोजन तक अलग ही तरह का होता है। ज्वालामुखी चाहे सक्रिय हो या ना हो, पर वहां के हालात बाकी दुनिया से बहुत अलग होते हैं। यहां की जमीन भी बहुत ही अलग तरह की होती है। वहीं अधिकांश ज्वालामुखी द्वीपों पर या फिर पानी के नीचे होते हैं। इसलिए ये जानवर तो पानी में रहने वाले होते हैं या फिर पानी के पास रहने वाले होते हैं। 1902 और 1932 में फ्रेंच द्वीप मार्टीनीक के माउंट पेली पर दो बार बहुत बड़ा ज्वालामुखी फूटा। फिर भी यहां एक मेंढक की प्रजाति जिसे मार्टीनीक वोल्केनो फॉग के नाम से जाना जाता है, जिंदा रह गए। विस्फोटों से इन मेंढकों पर अस्तित्व का संकट जरूर आ गया, लेकिन ये जिंदा रह गए थे। वोल्फ नाम के गैलापैगोस ज्वालामुखी द्वीप में सूखा और गर्मी होने के बावजूद यहां कुछ जानवर रहते हैं। लेकिन वैम्पायर ग्राउंड फिन्चेस के लिए यह जगह बहुत अच्छी है। इसके पीछे उनकी खुद को हालात के मुताबिक ढालने की क्षमता जिम्मेदार है। ये कैक्टस का पराग को खाती हैं और बूबी सीबर्ड का खून चूसती हैं। गैलोपैगोस द्वीपों के फेर्नानडीना द्वीप में कई विलुप्त होन का खतरा झेल रहे जानवर रहते हैं। इन्हीं में से एक गैलापैगोस येलो लैंड इगुआनास भी शामिल हैं। इनकी खास बात यह है कि ये ज्वालामुखी सक्रियता को पहचान लेते हैं। इससे ये ज्वालामुखी फूटने से पहले ही दूर सुरक्षित जमीन पर चले जाते हैं। तनजानिया के ओल डोन्यो लेन्गाई ज्वालामुखी के आसपास करीब 20 लाख लेसर फ्लेमिंगो रहते हैं। इनके पंख गुलाबी रंग के होते हैं और स्पिरूलिना नाम की पिगमेंट एल्गी खाते हैं जिससे इनके पंख गुलाबी होते हैं। जिस तालाब में रहते हैं वह दूसरे जानवरों के लिए रहने लायक बिलकुल नहीं है। लकिन लेसर फ्लेमिंगो के पैरों में एक परत उन्हें जलने से बचाती है। वे उबलते पानी में से नमक हटा कर पानी पी सकते हैं। हवाई के मौनुआ लोआ और किलौया ऐसे द्वीप हैं जहां बहुत सारी ओपिही देखने को मिलते हैं। ये जलीय घोंघे होते हैं जिनकी मजबूत पैर और शंकु के आकार की खोल होती है। ये चट्टानों पर चिपकी रहती हैं।पानी के अंदर जाकर इन्हें निकाले के चक्कर में सैकड़ों गोताखोरों की मौत हो चुकी है। इसी लिए इन्हें फिश ऑफ डेथ भी कहा जाता है। पोम्पेई वॉर्म ऐसे जीव हैं जो ज्वालामुखीय द्वार के अंदर ही रहते हैं। ये दुनिया में सबसे ज्यादा गर्मी झेल पाने वाले जानवर होते हैं। ये 105 डिग्री तक का तापमान झेलने में सक्षम हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि इनके शरीर पर छोटे बाल ज्वालामुखी वेंट के अंदर के गर्म माहौल में गर्मी से बचने में मदद करते हैं। कछुए की तरह ये भी अपना मुह अपने खोल से बाहर निकालते हैं। समुद्र के अंदर वॉल्केनिक जायंट ट्यूब वॉर्म समुद्री सतरह से निकलती गर्मी के कारण गर्म हुए पानी में रहते हैं। इसी गर्म पानी के खनिज इन कीड़ों के लिए पोषण का भी काम करते हैं। इन कीड़ों की आंतों में खास तरह के बैक्टीरीया होते हैं जो इन गर्म खनिजों को ऊर्जा में बदलते है। शिकारी जीवों से बचने के लिए ये अपनी ट्यूब को बंद भी कर सकते हैं। अगर इन्हें लंबे समय तक गर्मी ना मिले तो ये मर सकते हैं।

करोड़पति से की महिला ने शादी, अब बेटी के लिए अरबपति दूल्हे की मांग!

आपको दुनिया में अलग-अलग किस्म के लोग मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें अपनी पुश्तैनी दौलत से ज्यादा रुचि अपनी पहचान और अपनी प्रॉपर्टी बनाने में होती है। वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जो बिना कुछ किए ही करोड़ों-अरबों में खेलना चाहते हैं। खासतौर पर सोशल मीडिया के जरिये आप ऐसी तमाम महिलाओं को देखेंगे, जो करोड़पतियों से शादी करके अपनी रईसी दिखाती रहती हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि माता-पिता जो करते हैं, वही बच्चों को भी सिखाते हैं। ऐसे में एक करोड़पति शख्स की बीवी अपने बच्चों के लिए सीधी शर्त रख रही है कि उन्हें अपने लिए अरबपति ही चुनना होगा। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश एनफ्लुएंसर सौदी अल नदाक ने सोशल मीडिया पर बताया है कि वो अपने बच्चों के सुखद भविष्य के लिए उन्हें कुछ सलाहें ज़रूर देगी। सिर्फ पति के पैसों पर अपनी ज़िंदगी रईसी से जीने वाली सौदी का कहना है कि बच्चे सिर्फ उन्हीं को पैदा करने चाहिए, जो मेरी तरह अमीर हों। हालांकि वो ये भी बताती हैं कि उनके पास बहुत पैसा है लेकिन कम से कम बच्चों को बेहतरीन ज़िंदगी देने का पैसा न हो, तो उन्हें जन्म मत दो। इतना ही नहीं वो अपने बच्चों के लिए भी कुछ नियम सेट करके रखती हैं। उनके मुताबिक लड़की हो, तो उसे कहूंगी कि तुम खुद को अमीर मानो और शादी के लिए अपने से भी अमीर आदमी को चुनो। इससे ज़िंदगी आराम से कटेगी। अगर लड़का हो, तो उसे कहूंगी कि वो अपने पिता से पैसे बनाना सीखे और अमीरी की ज़िंदगी जिए। सौदी वैसे तो ब्रिटिश नागरिक थी लेकिन उसने अपने पति जमाल से शादी करने के बाद खुद को दुबई के रंग में ढाल लिया। वो महंगे कपड़े पहनती है और महंगे बैग्स और एक्सेसरीज लेकर घूमती है। वो खुद पति के पैसे उड़ाती है और उसका कहना है कि बेटी को भी वो पति के पैसों पर ऐश करना सिखाएगी। इतना ही नहीं उसका कहना है कि बच्चों के मुंह से माता-पिता के बजाय पहले महंगे ब्रांड्स के नाम सुनना चाहेगी। महिला की सोच पर वीडियो देखने वाले हैरान हैं।

पीएम मोदी आजकल लोगों को खूब बेवकूफ बना रहे : खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, बोले- हिंदी छोड़कर क्षेत्रीय भाषा बोलने लगे हैं

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि प्रधानमंत्री आजकल हिंदी छोड़ कर क्षेत्रीय भाषा में बोल कर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। दु:ख है कि संविधान को पूरी तरह से बीजेपी की ओर से स्वीकार नहीं किया गया है।

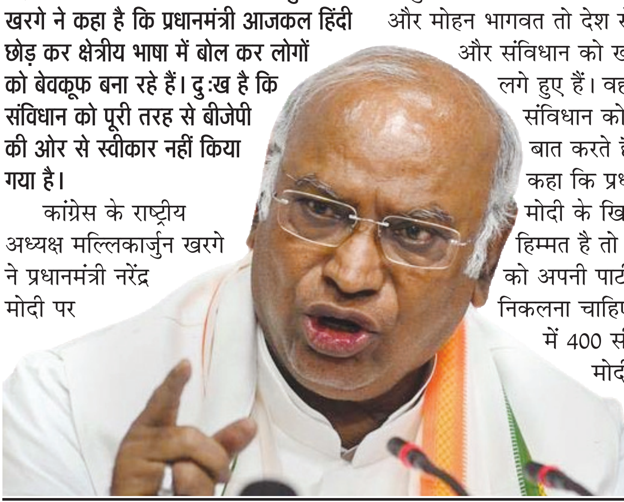

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा से सामाजिक न्याय के खिलाफ है और सेकुलरज्म के भी खिलाफ है। आरएसएस और मोहन भागवत तो देश से आरक्षण और संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। वह हमेशा से ही संविधान को बदलने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर हिम्मत है तो ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी से बाहर निकलना चाहिए क्या देश में 400 सीटों की बात मोदी जी देश में संविधान को बदलने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने दावा करते हुए आरोप लगाया कि आज भी आरएसएस तिरंगे झंडे को इतना मान नहीं देती है और केवल भगवे झंडे को ही महत्व देती है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर खरगे ने कहा कि एसबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट से समय मांगने से साफ हो गया कि मोदी सरकार काले कारनामे पर पर्दा डालना चाहती है। इतने समय की क्या जरूरत है? सरकार चुनाव तक सच छुपाना चाहती है।

संविधान बदलने की कोशिश होगी तो हंगामा होगा

पार्टी अध्यक्ष खरगे ने कहा कि कोई संविधान बदलने की कोशिश करेगा तो हंगामा होगा। संविधान बदलने की बात केरेंगे तो देश में हंगामा होगाा। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी इसके खिलाफ हैं तो चुप बैठने की बजाय ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर करना चाहिए, हम इस तरह के प्रयासों की निंदा करते हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए यह भी आरोप लगाया कि वो अपने नेताओं से कहलवाते हैं कि संविधान बदलने के लिए दो तिहाई बहुमत दो, ऐसा बीजेपी के सांसद बोल रहे हैं, उन्होंने दोहराया है कि संविधान को बदलना चाहिए।

जल्द पकड़ में होगा बेंगलुरु विस्फोट का संदिग्ध : परमेश्वर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

बेंगलुरु । कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि एक मार्च को शहर के मशहूर रेस्तरां द रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट से संबंधित मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने एक तरह से संदिग्ध की पहचान कर ली है और उसे पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि जांचकर्ता संदिग्ध की पहचान की पुष्टि कर रहे हैं और उसके करीब पहुंच रहे हैं।

» गृहमंत्री का दावा-आरोपी की पहचान हुई

पूर्वी बेंगलुरु के ब्रुकफील्ड क्षेत्र में स्थित रेस्तरां में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) से हुए विस्फोट की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) कर रहा है जबकि बेंगलुरु पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) इसमें सहायता कर रही है। विस्फोट में 10 लोग घायल हुए थे। परमेश्वर ने यहां पत्रकारों से कहा, जांच की जा रही है, हम करीब पहुंच रहे हैं, एक तरह से उस व्यक्ति (संदिग्ध) की पहचान कर ली गई है। पहचान की पुष्टि करके उसे पकड़ना है। वे यह कर रहे हैं, एनआईए यह कर रही है और सीसीबी उनके साथ यह कर रही है। उन्हें काफी सुराग मिले हैं।

महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका

साईबाबा को बरी करने के आदेश पर रोक से इनकार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा और अन्य को माओवादी संबंध मामले में बरी कर दिया गया था।

पीठ ने अपील को जल्द सूचीबद्ध करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के मौखिक अपील को भी खारिज कर दिया और कहा कि यह सही समय पर आएगा।

पीठ ने एसवी राजू ने कहा कि सजा को पलटने के आदेश में कोई जल्दबाजी नहीं की जा सकती। अगर यह दूसरा तरीका होता, तो हम इस पर विचार करते।

हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा की थी रद्द

गौरतलब है कि पांच मार्च को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने 54 वर्षीय साई बाबा और अन्य को बरी कर दिया, यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। हाईकोर्ट ने साईबाबा की आजीवन कारावास की सजा को भी रद्द कर दिया था और मामले में पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था।

शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजद्रोह और गैरकानूनी गतिविधियों (यूएपीए) के आरोपों समेत वर्ष 2020 के सांप्रदायिक दंगों के मामले के संबंध में जमानत देने का अनुरोध करने वाले छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम की याचिका पर सोमवार को पुलिस से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने इमाम की जमानत याचिका खारिज करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उसकी याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।

आईएएस गौरव द्विवेदी को लंदन में मिला सम्मान

इंडिया यूके- अचीवर्स ऑनर्स से सम्मानित

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

रायपुर। छत्तीसगढ़ कैडर के 95 बैच के आईएएस ऑफिसर और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे गौरव द्विवेदी को लंदन में सम्मानित किया गया है। श्री द्विवेदी को इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनी यूनियन यूके द्वारा प्रदान किया गया। इस आयोजन में भारत में ब्रिटिश काउंसिल की भी साझेदारी रही।

यह सम्मान श्री द्विवेदी को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के लिए फिल्म नीति के निर्माण और सफलतापूर्वक कार्यान्वयन की दिशा में उनके अनुकरणीय कार्य के लिए समाज और नीति की श्रेणी में दिया गया है। उल्लेखनीय है कि, नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनी यूनियन यूके (एनआईएसएयू) के द्वारा भारत में ब्रिटिश काउंसिल की साझेदारी और यूके उच्च शिक्षा क्षेत्र का भी सहयोग इस आयोजन में रहता है।

मुझे यूके-भारत साझेदारी पर बेहद गर्व है : पीएम सुनक

इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स के इस आयोजन पर टिप्पणी करते हुए, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा- सबसे पहले मैं आपको उन सभी के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप विशेष यूके-भारत साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि दूसरे वर्ष भी आप ब्रिटेन में विकसित असाधारण भारतीय प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे यूके-भारत साझेदारी पर बेहद गर्व है।

आयोजन से रिश्ते होंगे मजबूत

इस सम्मान समारोह का आयोजन विश्व स्तर पर यूके के पूर्व छात्रों की उपलब्धियों का जश्न मनाने, शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधों में भारत और यूके के बीच आगे सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, अपने क्षेत्र और समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भारतीय यूके के पूर्व छात्रों को लंदन में इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित किया गया।

सूर्यकुमार आईपीएल के शुरुआती मैच नहीं खेलेंगे शमी भी टूर्नामेंट से बाहर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। टीम इंडिया के स्टार बैटर सूर्यकुमार यादव आईपीएल के शुरुआती 2 मैचों से बाहर हो सकते हैं। वे अब तक इंजरी से रिकवर नहीं कर सके हैं, उनके फिट होने के बारे में भी एनसीए या बीसीसीआई ने अब तक कोई जानकारी नहीं दी है।

सूर्यकुमार से पहले दिल्ली कैपिटल्स के ऋषभ पंत का भी आईपीएल के सभी मैचों में शामिल होना मुश्किल बताया गया। वहीं गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी तो टूर्नामेंट से बाहर ही हो गए हैं। सूर्या आईसीसी की टी-20 बैटर्स रैंकिंग में नंबर-1 प्लेयर हैं। वे मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल खेलते हैं।

अनुशासनहीनता के आरोप में लामार्टिनियर ब्वॉयज कालेज के 11 शिक्षक बर्खास्त

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। लामार्टिनियर ब्वॉयज कॉलेज के 11 शिक्षकों का सेवा से हटा दिया गया है। प्रधानाचार्य सी मैकफारलैंड ने सभी की बर्खास्तगी का आदेश जारी किया। इन सभी शिक्षकों के कॉलेज आने पर रोक लगा दी गई है। इन पर प्रधानाचार्य कक्ष में तालाबंदी, पोस्टर जलाने और अनुशासनहीनता का आरोप है। इस सम्बंध में ट्रस्ट की सदस्य मण्डलायुक्त डॉ. रोशन जैकब से बात करने का प्रयास किया गया लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ।

ला मार्टिनियर ब्वॉयज में प्रिंसिपल और शिक्षकों के बीच चल रहा विवाद थम नहीं रहा है। बर्खास्त शिक्षकों में दो मिडिल स्कूल तथा नौ सीनियर स्कूल के असिस्टेंट टीचर हैं। यह कार्रवाई दिसम्बर 2023 में प्रधानाचार्य कक्ष में ताला जड़ने, शिक्षकों द्वारा प्रेस कांन्फ्रेंस कर आरोप लगाने, आपत्तिजनक व्यवहार और पोस्टर लगाने पर की गई है। प्रिंसिपल सी. मैकरफारलैंड के जारी पत्र के अनुसार शिक्षकों को एक जनवरी को चार्टशीट दी गई थी और सभी पर लगे आरोप सही पाए गए हैं। मामले में आरोप पत्र दायर करने वालों में मिडिल स्कूल की प्रमुख जी. लोबो भी शामिल थीं, जिन्होंने इसके बाद इस्तीफा दे दिया था। वहीं, कॉलेज के बर्सर एड्रियन माइकल की संलिप्तता की जांच चल रही है।

सीएए पर सड़क से अदालत तक संग्राम

» दिल्ली समेम कई राज्यों में अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात, असम में आज बंद

» कानून के खिलाफ मुस्लिम लीग ने दायर की याचिका

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। देशभर में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम यानी कि सीएए कानून लागू होते सड़क से शीर्ष अदालत तक विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गयें हैं। विरोध को दखते हुए कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश असम और दिल्ली उन संवेदनशील राज्यों में शामिल हैं, यहां पुलिस अलर्ट मोड पर है। मंगलवार को कई जगह बाजार बंद रहे है। वंही प्रदशर्न के बीच सीएए पर रोक लगाने के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई है।दिल्ली पुलिस की साइबर बिंग भी अलर्ट पर है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर देश भर की सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस की पैनी नजर है।

दरअसल सीएए के विरोध में राजधानी में बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन किया गया था। शाहीनबाग इलाके पर खास नजर रखी जा रही है। वहीं असम में सीएए के खिलाफ आज बंद बुलाया गया है। बंगाल में हालांकि सीएए के आने के बाद खुशी नृत्य करते लोग नजर आए। सीएए के नियमों को अधिसूचित करने के बाद गौतमबुद्धनगर पुलिस अलर्ट मोड पर है. तीनों जोन के पुलिस उपायुक्तों (डीसीपी) ने सोमवार शाम को पुलिसबल के साथ अलग-अलग जगहों पर पैदल मार्च किया।अधिकारियों ने बताया कि संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है तथा इन इलाकों में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पुलिस सभी धर्म गुरुओं के साथ पहले ही बैठक कर चुकी है तथा कई जगह पर सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। नोएडा जोन के डीसीपी विद्या सागर मिश्रा ने बताया कि शहर के कई हिस्सों में ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है तथा शहर को 'जोन और 'सुपरजोन में बांटा गया है।

दिल्ली व एनसीआर में अलर्ट

सोशल मीडिया पर भी नजर

पुलिस अधिकारी ने कहा कि सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए दो दल गठित किए गए हैं और अगर किसी ने माहौल खराब करने वाला वीडियो साझा किया और ऐसी टिप्पणी की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में गश्त करने का निर्देश दिया गया है।

असम में16 विपक्षी राजनीतिक दलों को कानूनी नोटिस

ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने सीएए के विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया है। 16 दलों के संयुक्त विपक्षी फ़ोरम ने आज राज्यव्यापी बंद का एलान किया है। असम में कुछ जगह सीएए की प्रतियां भी जलाई गईं। एएसयू से जुड़े लोग दिल्ली आकर सरकार से सीएए की अधिसूचना वापस लेने की अपील करेंगे।असम पुलिस ने बंद बुलाए जाने पर 16 विपक्षी राजनीतिक दलों को कानूनी नोटिस जारी किया है। पुलिस ने राजनीतिक दलों को चेतावनी देते हुए कहा कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, बंद में शामिल लोगों पर केस दर्ज किए जा सकते हैं। पुलिस ने सख्त लहजे में कहा कि विरोध-प्रदर्शन और बंद की वजह से अगर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो उनकी वसूली भी प्रदर्शनकारियों से ही की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाने की मांग

सुप्रीम कोर्ट में सीएए कानून के खिलाफ याचिका दायर की गई है। यह याचिका इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से दायर की गई है, जिसमें कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। सीएए (नागरिकता संशोधन कानून)अधिसूचना का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है। सीएए अधिसूचना को लागू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। ये याचिका आईयूएमएल ने दाखिल की है। आईयूएमएल ने अधिसूचना के कार्यान्वयन पर रोक की मांग की है। आईयूएमएल ने कहा कि सीएए असवैधानिक, मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण है। आईयूएमएल के मुताबिक- पहले सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने यह कहते हुए रोक का विरोध किया था कि कोई तत्काल कार्यान्वयन नहीं होगा क्योंकि नियम अधिसूचित नहीं है।उनकी ओर से कहा गया कि सीएए असवैधानिक है और मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण है. धार्मिक पहचान के आधार पर वर्गीकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। वहीं डेमोक्रेटिक यूथ फ्रंट ऑफ इंडिया भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सीएए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली अपनी लंबित याचिका पर सुनवाई की मांग कर सकता है।

मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने किया समर्थन

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने सीएए नोटिफिकेशन जारी होने का स्वागत किया और कहा कि यह बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था। इस कानून को लेकर मुस्लिमों में बहुत गलतफहमी है। इस कानून का मुस्लिमों से कोई लेना-देना नहीं है। पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर-मुस्लिमों को भारत की नागरिकता देने का कोई प्रावधान नहीं था। यही वजह है कि ये कानून बनाया गया। देश के करोड़ों मुसलमान इस कानून से प्रभावित नहीं होंगे और इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। बीते वर्षों में गलतफहमी की चलते विरोध प्रदर्शन हुए। कुछ राजनेताओं ने मुस्लिमों में गलतफहमी को बढ़ावा दिया और देश के हर मुसलमान को इस कानून का स्वागत करना चाहिए।

कई आईएएस अधिकारी इधर से उधर

» रमेश रंजन होंगे फिरोजाबाद के डीएम

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर किया है। यूपी सरकार ने फिरोजाबाद के डीएम को हटा दिया है। प्रदेश सरकार ने कुछ आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव किया है। जानकारी के अनुसार, प्रदेश सरकार ने फिरोजाबाद के जिलाधिकारी उज्जवल कुमार को हटा दिया है। उन्हें विशेष सचिव सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग बनाया गया है।

कौशल विकास विभाग में विशेष सचिव रमेश रंजन को फिरोजाबाद का डीएम बनाया गया है। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग में विशेष अरुण प्रकाश को नगर विकास विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। अपर निदेशक सहकारिता ईशा प्रिया को विशेष सचिव पर्यटन बनाया गया है। विशेष सचिव गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग शेषनाथ को विशेष सचिव पीडब्ल्यूडी बनाया गया है। विशेष सचिव युवा कल्याण गौरव वर्मा को विशेष सचिव सचिवालय प्रशासन बनाया गया है।

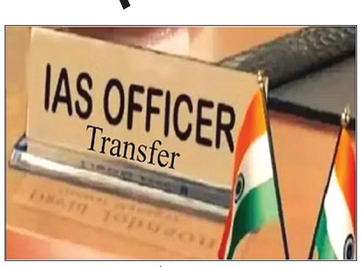

किसान आंदोलन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। किसान आंदोलन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जाने को कहा है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को पता होना चाहिए कि हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। जब हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश भी जारी कर दिए तो आप सुप्रीम कोर्ट में समानांतर कार्रवाई क्यों चाहते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जैसे ही इस मामले में दखल देगा तो हाईकोर्ट अपने हाथ खड़े कर लेगा तो इससे किसका उद्देश्य पूरा होगा। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चंडीगढ़ से कुछ दूरी पर है इसीलिए वह हाईकोर्ट जाकर अपनी बात रख सकते हैं।

गाजीपुर हादसा: 3 अधिकारी निलंबित एक की सेवा समाप्त

» बस पर गिरा था हाइटेंशन का बिजली तार, 5 की मौत, कई गंभीर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। यूपी के गाजीपुर जिले में सोमवार को एक बस के हाईटेंशन बिजली के तार के संपर्क में आने से बस में आग लग गई। आग से पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग झुलस गए हैं, घटना की जानकारी होने पर ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए. के. शर्मा ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने तीन अधिकारियों को निलंबित और एक की सेवा समाप्त कर दी है।

घटना की जानकारी मिलते ही मंत्री ए.के. शर्मा ने सख्त कार्रवाई करते हुए अधिशासी अभियंता मनीष, एसडीओ संतोष चौधरी और जेई प्रदीप कुमार राय को निलंबित और लाइनमैन नरेंद्र (संविदा कर्मी) की सेवा समाप्ति के निर्देश दिए। उन्होंने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी एवं अधीक्षण अभियंता से बात की। सभी अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाते हुए घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था सहित प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया।

'वो सीएए की बात करेंगे, तुम इलेक्टोरल बॉण्ड पर अड़े रहना'

» नेहा सिंह राठौर ने कविता के माध्यम से किया विरोध

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नोएडा। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा लागू किया जा चुका है। सीएए लागू होने के बाद भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर ने प्रतिक्रिया दी है।नेहा सिंह राठौर ने कहा, वो सीएए की बात करेंगे, तुम इलेक्टोरल बॉण्ड पर अड़े रहना। हालांकि बीते लंबे वक्त से भोजपुरी सिंगर बीजेपी सरकार को उसकी नीतियों पर घेरती रही हैं, इससे पहले उन्होंने कहा था, देश को बधाई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी कल तक देनी होगी।

जो पहले विदेशी बैंकों से कालाधन लाने के दावे करते थे, वो आज अपने कालेधन का हिसाब एसबीआई से बाहर नहीं आने दे रहे। उन्होंने कहा था, इनकी प्राथमिकता सूची में आपके मुद्दे कहां होंगे? इनको देशभर में फैली बेरोज़गारी और मंहगाई जैसी समस्याओं से कितना फर्क पड़ता होगा? आपकी दाल-रोटी या आपके बच्चे की पढ़ाई और स्वास्थ्य के मुद्दे से इनको कितना मतलब होगा? सिंगर ने सोशल मीडिया पर किए गए इस पोस्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी शेयर की थी।

पीएम मोदी की फोटो शेयर कर लिखी ये बात

दक्षिण फिल्मों के एक्टर विजय ने सीएए कानून को अस्वीकारा

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू करने पर साउथ अभिनेता दलपति विजय ने अपनी नाराजगी जाहिर की और इसे अस्वीकार्य बताया है। तमिल अभिनेता और तमिलागा वेट्री कड़गम (टीवीके) प्रमुख थलपति विजय ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 लागू करने के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला बोला। अभिनेता ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को अस्वीकार्य बताया और तमिलनाडु सरकार से इसे राज्य में लागू नहीं करने का अनुरोध किया है। विजय ने अपनी पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम (टीवीके) के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक आधिकारिक बयान साझा किया है। उन्होंने तमिल में लिखा, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (सीएए) जैसे किसी भी कानून को ऐसे माहौल में लागू करना स्वीकार्य नहीं है, जहां देश के सभी नागरिक सामाजिक सद्भाव के साथ रहते हैं। नेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह कानून देश में लागू न हो।

स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक संजय शर्मा द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित एवं 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। संपादक - संजय शर्मा, विधि सलाहकार: सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, मोहम्मद हैदर, वित्तीय सलाहकार: संदीप बंसल, कार्टूनिस्ट: हसन जैदी, दूरभाष: 0522- 4078371 | Email: daily4pm@gmail.com | website: www.4pm.co.in |
RNI-UPHIN/2015/62233 डाक पंजी. सं- SSP/LW/NP-495/2018-2020 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।